



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 2019/कार्तिक 16, 1941

No. 392]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 2019/KARTIKA 16, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 22 अक्टूबर, 2019

सं. टीएमपी/25/2018-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से आईसीडी कंटेनरों की निशुल्क अवधि में घटौती करने का अनुमोदन चाहने के प्रस्ताव का संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएमपी/25/2018-जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

...

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्टूबर, 2019 के 10वें दिन पारित)

यह मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से आईसीडी कंटेनरों की निशुल्क अवधि को 7 दिन से घटा कर 3 दिन करने के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. जेएनपीटी द्वारा 5 अप्रैल, 2018 के अपने प्रस्ताव में उठाये गए मुख्य मुद्दों का सारांश इस प्रकार है:-

- (i) रेल द्वारा मूव किये जाने वाले एकजिम कंटेनरों के लिए जे एन पत्तन की मौजूदा निशुल्क अवधि 7 दिन है। सड़क मार्ग द्वारा ढुलाई किये गए औसत ठहराव समय की तुलना में रेल द्वारा मूव किये गए एकजिम कंटेनरों का औसत पिछले ठहराव समय पिछले तीन महीने से उच्चता की ओर है।

माह	सड़क द्वारा आयात औसत ठहराव समय घंटों में	रेल द्वारा आयात औसत ठहराव समय घंटों में	सड़क द्वारा निर्यात औसत ठहराव समय घंटों में	रेल द्वारा निर्यात औसत ठहराव समय घंटों में
दिसंबर-17	32.44	68.81	77.56	103.19
जनवरी-18	31.43	90.90	69.87	103.22
फरवरी-18	30.88	94.80	73.64	111.70
औसत	31.58	84.84	73.69	106.04

- (ii) रेल द्वारा मूव किये गए कंटेनरों के लिए एक्जिम कंटेनरों के उपरोक्त अधिक समय पर 26.06.2017 को नीति आयोग की बैठक में चर्चा की गई थी। जे एन पत्तन के रेल द्वारा ढुलाई किये जाने वाले कंटेनरों के ठहराव समय को घटा कर सड़क मार्ग के समान लाने की राय का नीति आयोग ने समर्थन किया। 01.03.2018 को आयोजित हुए एक बैठक में माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव ने भी यह टिप्पणी की कि कार्गो ढुलाई में रेलवे का नियंत्रण सारे पत्तन परिस्थिति की व्यवस्था पर प्रपाती प्रभाव डालता है और निर्देश किया कि "यदि रेलवे 3 दिन की अवधि में कंटेनरों की ढुलाई करने में सक्षम नहीं होता है, तो ढुलाई का उत्तरदायित्व परिवहन के अन्य साधनों को परिवर्तित किया जाना चाहिए।"।

2.2. तदनुसार, जेएनपीटी ने अनुरोध किया है कि रेल द्वारा मूव किये जाने वाले एक्जिम कंटेनरों की निशुल्क अवधि को उनके दरमानों में मौजूदा 7 दिन से घटाकर 3 दिन कर दी जाए जिससे यह सड़क मार्ग ठहराव समय के समान हो जाए।

2.3. हमारे द्वारा 9 अप्रैल, 2018 के पत्र के द्वारा किये गए विशिष्ट अनुरोध के आधार पर और तत्पश्चात् 27 अप्रैल, 2018 और 17 मई 2019 के अनुस्मारकों के पश्चात् जेएनपीटी ने 2 जुलाई, 2018 के पत्र के द्वारा संदर्भाधीन प्रस्ताव के संबंध में प्रारूप दरमान और न्यासी मंडल के अनुमोदन की प्रति भेजी।

2.4. जेएनपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रारूप दरमान इस प्रकार हैं:-

पत्तन परिसर में भंडारित कंटेनरों के ठहराव समय प्रभार:-

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका एक भाग (अमरीकी डॉलर में) विदेशी		दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका एक भाग (अमरीकी डॉलर में) तटीय	
		लंबाई में 20' तक	लंबाई में 20' से 40' तक	लंबाई में 20' तक	लंबाई में 20' से 40' तक
5.	आईसीडी निर्यात व आयात – लदे अथवा खाली रेल द्वारा ढुलाई।				
	प्रथम 3 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
	4-15 दिन	3.2797	6.5555	143.04	286.07
	16-30 दिन	3.9515	7.9030	172.30	344.60
	31-45 दिन	7.9030	15.8061	344.60	690.83
	तत्पश्चात्	15.8061	31.6122	690.83	1380.03

टिप्पणी : उक्त दरें 13 सितंबर, 2017 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 356 में प्रकाशित प्राधिकरण के आदेशानुसार हैं।

2.5. मौजूदा व्यवस्था और प्रस्तावित व्यवस्था की तुलनात्मक स्थिति नीचे सारणीबद्ध की जाती हैं:-

क्र.सं.	मौजूदा व्यवस्था				प्रस्तावित व्यवस्था			
	विवरण	दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका एक भाग (अमरीकी डॉलर में) विदेशी		दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका एक भाग (अमरीकी डॉलर में) तटीय	विवरण	दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका एक भाग (अमरीकी डॉलर में) विदेशी		दर प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका एक भाग (अमरीकी डॉलर में) तटीय
		लंबाई में 20' तक	लंबाई में 20' से 40' तक			लंबाई में 20' तक	लंबाई में 20' से 40' तक	
5.	आईसीडी निर्यात व आयात – लदे अथवा खाली रेल द्वारा ढुलाई।				आईसीडी निर्यात व आयात – लदे अथवा खाली रेल द्वारा ढुलाई।			
	प्रथम 7 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	प्रथम 3 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
	7-15 दिन	3.2797	6.5555	143.04	4-15 दिन	3.2797	6.5555	286.07
	16-30 दिन	3.9515	7.9030	172.30	16-30 दिन	3.9515	7.9030	344.60
	31-45 दिन	7.9030	15.8061	344.60	31-45 दिन	7.9030	15.8061	690.83
	तत्पश्चात्	15.8061	31.6122	690.83	तत्पश्चात्	15.8061	31.6122	1380.03

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, जेएनपीटी के 5 अप्रैल 2018 और 2 जुलाई 2018 के प्रस्ताव संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्त संगठनों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजी गई थीं। इस संबंध में कुल्लेक संघों ने नामतः मुंबई एंड न्हावा शेवा शिप एजेंट्स एसोसिएशन (एमएनएसए), इंडियन नैशनल शिप आनर्स एसोसिएशन (आईएनएसए) और इंडियन मर्चेंट चैंबर (आईएमसी) ने अपनी टिप्पणियां भेजी। इन टिप्पणियों को फीडबैक सूचना के तौर पर जेएनपीटी को भेजा गया। जेएनपीटी ने 30 अगस्त 2018 और 16 मई 2019 के पत्र के द्वारा अपना प्रत्युत्तर दिया।

4. बाद में जेएनपीटी ने 9 अगस्त, 2018 के पत्र के द्वारा अध्यक्ष, जेएनपीटी के तत्वावधान में और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 6 जुलाई 2018 को हुई बैठक तथा उक्त बैठक में जेएनपीटी के अधिकारियों और प्रयोक्ताओं में हुई चर्चा के कार्यवृत्त भेजे। बैठक के कार्यवृत्तों से यह देख गया कि अन्य बातों के साथ-साथ यह चर्चा हुई थी कि आईसीडी कंटेनरों की निशुल्क अवधि को चरणबद्ध ढंग से कम किया जाए और कि यह कॉंकर और अन्य कंटेनर टर्मिनल प्रचालकों से फीडबैक पर आधारित था, निशुल्क अवधि घटाने के लिए कुछेक आईसीडी का पता लगाया गया।

5. जेएनपीटी को हमारे 19 जुलाई, 2018 के पत्र के द्वारा कुछ सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया। तदनुसार जेएनपीटी ने 11 सितंबर, 2018 के पत्र के द्वारा प्रत्युत्तर दिया। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना और जेएनपीटी द्वारा दिया गया उत्तर नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना	जेएनपीटी द्वारा दिया गया उत्तर
(i)	वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से रेल द्वारा मूव किये जाने वाले कंटेनरों का ठहराव समय सड़क मार्ग से ढोये जाने वालों से अधिक होता है।	रेल से ढोये जाने वाले कंटेनरों के अधिक ठहराव समय के कारण है:- (i) निजी रेल प्रचालकों/के पास आयतन कम होता है और उन्हें रेल पूरी करने में लंबा समय लगता है। (ii) कुछ आईसीडी का निर्यात और आयात कार्गो कम होता है। (iii) आयतन में वृद्धि के दौरान गाड़ी प्रचालक कॉनकर अतिरिक्त रेल गुटाने में असमर्थ रहता है।
(ii)	आईसीडी कंटेनरों के लिए निशुल्क अवधि को 7 दिन से घटाकर 3 दिन करने से जेएनपीटी को अतिरिक्त आय होगी। इस संबंध में आकलित अतिरिक्त आय 31 मार्च 2019 तक की शेष प्रशुल्क वैधता अवधि के लिए निर्धारित की जायेगी।	आईसीडी कंटेनरों के लिए निशुल्क अवधि को 7 दिन से घटाकर 3 दिन करने से जेएनपीटी को होने वाली अतिरिक्त आय लगभग 5.52 करोड़ रु. प्रति वर्ष होगी।
(iii)	यह स्मरण कराया जाता है कि 4 जनवरी 2017 के आदेश संख्या टीएमपी/48/2016-जेएनपीटी के द्वारा निपटान किये गए जेएनपीटी के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव में प्रशुल्क के तत्समय प्रस्तावित स्तर पर जेएनपीटी द्वारा आकलित आय अधिकतम वार्षिक राजस्व अपेक्षा के समान ही 843.28 करोड़ रु. ही थी। दूसरे शब्दों में प्रशुल्क के तत्समय प्रस्तावित स्तर पर जेएनपीटी द्वारा आकलित आय और अधिकतम एआरआर में कोई राजस्व अंतर नहीं था। यह उक्त एआरआर पर आधारित था और 2014-15 के आतायात को हिसाब में लेकर जेएनपीटी में प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए जेएनपीटी द्वारा निर्धारित की गई थी। इस बात पर सुविचार करते हुए कि ठहराव समय में कमी होने से पत्तन को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी जेएनपीटी कुछ अन्य प्रशुल्क मदों की दरों में समायोजन का प्रस्ताव करेगा। ताकि ठहराव समय में कमी के कारण होने वाला अतिरिक्त राजस्व अधिकतम एआरआर के भीतर ही रहे जैसा कि जेएनपीटी के जनवरी 2017 में निर्धारित किया गया था और राजस्व यथावत बना रहे।	यह निवेदन किया जाता है कि प्राधिकरण ने 843.28 करोड़ रु. की अधिकतम वार्षिक राजस्व अपेक्षा की मंजूरी दी है और परिणामस्वरूप कंटेनर संबंधी प्रश्नों में 16% वृद्धि की मंजूरी दी। फिर भी, व्यापार के हित में पत्तन ने दरों में वृद्धि नहीं की और पत्तन ने 4 अप्रैल, 2014 के प्रशुल्क आदेश में स्वीकृत दरों को ही बनाए रखा। अतः यह निवेदन किया जाता है कि यदि ठहराव समय में कमी करने से पत्तन को अतिरिक्त राजस्व होता भी है तो कुछ अन्य प्रशुल्क मदों की दरों में समायोजन की जरूरत नहीं है ताकि ठहराव समय में कमी के कारण होने वाला अतिरिक्त राजस्व अधिकतम एआरआर के भीतर ही रहे और राजस्व यथावत बना रहे।

6. संदर्भाधीन मामले में 20 जुलाई 2018 को प्राधिकरण के मुंबई स्थित कार्यालय में संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में, जेएनपीटी और प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने अपने-अपने निवेदन रखे।

7.1. तत्पश्चात् जेएनपीटी ने 15 दिसंबर 2018 के अपने पत्र के द्वारा बताया है कि मुंद्रा और पिपावाव द्वारा भंडारण अवधि में पेन इंडिया आधार पर कमी करने के पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के प्रस्ताव से असहमति को देखते हुए, जेएनपीटी ने रेल कंटेनरों के लिए मौजूदा निशुल्क अवधि को बनाये रखने का अनुरोध एमओएस से किया है।

7.2. अतः यह विचार में, लेते हुए कि निजी प्रचालकों ने आईसीडी कंटेनरों की निशुल्क अवधि को घटाने से मना कर दिया है और एमओएस को भी यह संसूचित किया है कि वह आईसीडी कंटेनरों की मौजूदा निशुल्क अवधि को बनाए रखना चाहते हैं आदर इस मामले में एमओएस से सूचना की प्रतीक्षा में हैं। तदनुसार, जेएनपीटी ने हमें अनुरोध किया कि एमओएस से अगले आदेश प्राप्त होने तक मामले को आस्थित रखा जाए।

8. इस संबंध में, 09 अप्रैल 2019 को एक अनुस्मारक के पश्चात् जेएनपीटी ने 16 मई, 2019 के अपने पत्र के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किया:

- (i) पत्तन के 6.11.2018 पत्र संख्या जीएनपी/ट्रेफिक/आईसीडी/2018/2877 के उत्तर में पोत परिवहन मंत्रालय ने 12.12.2018 के अपने पत्र संख्या पीडी- 14033/30/2018-पीडी-V के द्वारा उत्तर दिया कि रेल द्वारा आने वाले कार्गो के ठहराव समय में घटौती के प्रस्ताव का कार्यान्वयन चरण-वार किया जाए और पहले चरण में कॉनकर के 3 आईसीडी के लिए निशुल्क समय को घटाकर 4 दिन कर दिया जाये।

- (ii) मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, जेएन पत्तन ने कॉनकर को निशुल्क अवधि में घटौती के लिए 3 आईसीडी गंतव्य स्थानों का पता लगाकर जेएनपीटी को सूचित करें ताकि प्राधिकरण से संपर्क किया जा सके। कॉनकर का उत्तर प्रतीक्षित है।

9.1. जेएनपीटी से उक्त उत्तर प्राप्त होने के पश्चात्, हमें आज तक जेएनपीटी ने कुछ नहीं बताया है।

9.2. यह ध्यान देने योग्य है कि, जेएनपीटी द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोध पर हमने जेएनपीटी के प्रस्ताव को आस्थगित रखने का निर्णय लिया था। आज तक हमें जेएनपीटी ने रेल द्वारा आने वाले कार्गो के ठहराव समय की चरणवार घटौती का पता लगाने में कॉनकर के 3 आईसीडी के बारे में कोई सूचना नहीं दी है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि जेएनपीटी द्वारा आरंभिक प्रस्ताव अप्रैल 2018 में दायर किया गया था। 20 जुलाई 2018 को संयुक्त सुनवाई का भी आयोजन किया गया। जेएनपीटी का प्रस्ताव 17 महीनों से भी अधिक समय से हमारे पास जेएनपीटी से सूचना और स्पष्टीकरण के अभाव में लंबित पड़ा है।

9.3. तदनुसार, जेएनपीटी को हमने 19 जुलाई 2019 के पत्र के द्वारा निशुल्क अवधि में घटौती के कॉनकर के 3 आईसीडी का पता लगाने पर कॉनकर का प्रत्युत्तर 31 जुलाई 2019 तक भेजने का अनुरोध किया गया था, असफल रहने पर प्राधिकरण को जेएनपीटी से वांछित सूचना के अभाव में मामले को बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उक्त पत्र के बावजूद जेएनपीटी ने अब तक वांछित सूचना नहीं दी है।

10.1. यह प्रस्ताव हमारे पास 17 महीने से भी अधिक समय से लंबित है। यह दिया गया है कि समयबद्ध रूप से आदेश पारित करने के बारे में विभिन्न दिशानिर्देशों में समयसीमा निर्धारित की गई है। इसलिए यह उपयुक्त नहीं समझा जाता कि जेएनपीटी के प्रस्ताव को पत्तन से सूचना के अभाव में अनिश्चित काल तक लंबित रखा जाए। यहां तक कि जेएनपीटी को अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी, जेएनपीटी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उक्त स्थिति को देखते हुए, यह प्राधिकरण जेएनपीटी से वांछित सूचना के अभाव में इस मामले को बंद करने को बाध्य है।

10.2. भविष्य में, इस विषय पर जेएनपीटी से प्राप्त किसी पत्र को नया मामला समझा जायेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./279/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd October, 2019

No. TAMP/25/2018-JNPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), seeking approval for reduction in free period for ICD containers, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/25/2018- JNPT

Jawaharlal Nehru Port Trust

...

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 10th day of October, 2019)

This case relates to a proposal received from the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) for reduction in free period for ICD containers from 7 days to 3 days.

2.1. The main points made by JNPT in its proposal dated 5 April 2018 are summarized below:

- (i) The existing free period at JN Port for EXIM containers moved by rail is 7 days. The average dwell time of EXIM containers for the last three months moved by rail are on a higher side as compared to the average dwell time by road which is detailed below:

Month	Import by Road Avg. Dwell Time in Hrs.	Import by Rail Avg. Dwell Time in Hrs.	Export by Road Avg. Dwell Time in Hrs.	Export by Rail Avg. Dwell Time in Hrs.
Dec-17	32.44	68.81	77.56	103.19
Jan-18	31.43	90.90	69.87	103.22
Feb-18	30.88	94.80	73.64	111.70
Average	31:58	84.84	73.69	106.04

- (ii) The above high dwell time for EXIM containers moved by rail was discussed in the NITI Aayog meeting convened on 26.06.2017 and JN Port's view for reducing the dwell time of containers moved by rail on par with road was supported by NITI Aayog. Also, the Principal Secretary to Hon'ble Prime Minister in a meeting held on 01.03.2018 has observed that the limitation of Railways in cargo transportation is leading to cascading effect on the entire port eco- system and has directed that "if the Railways are not able to transport the containers within 3 days period, the responsibility of transportation should be diverted to other modes of transport".

2.2. Accordingly, the JNPT has requested that an amendment may be made in its Scale of Rates (SOR) to reduce the free period of EXIM containers moved by rail from the existing 7 days to 3 days, so as to bring it on par with road dwell time.

2.3. Based on a specific request made by us vide our letter dated 9 April 2018 and followed by reminders dated 27 April 2018 and 17 May 2018, the JNPT vide its letter dated 2 July 2018 has furnished draft Scale of Rates and copy of approval of Board of Trustees with regard to the proposal in reference.

2.4. The draft Scale of Rates furnished by JNPT is as follows:

Dwell Time Charges for Container stored in the Port Premises:

Sr. No.	Particulars	Rate per container per day or part thereof (in US\$) Foreign		Rate per container per day or part thereof (in ₹) Coastal	
		Up to 20' in length	Over 20' to upto 40' in length	Up to 20' in length	Over 20' to upto 40' in length
5.	ICD Import & Export- Loaded or Empty moved by Rail				
	First 3 days	Free	Free	Free	Free
	4-15 days	3.2797	6.5555	143.04	286.07
	16-30 days	3.9515	7.9030	172.30	344.60
	31-45 days	7.9030	15.8061	344.60	690.83
	Thereafter	15.8061	31.6122	690.83	1380.03

Note : The aforesaid rates are as per TAMP Order published in Gazette notification No. 356 dated 13th September 2017.

2.5. A comparative position of the existing provision and proposed provision is tabulated below:

Sr. No.	Existing Provision					Proposed Provision				
	Particulars	Rate per container per day or part thereof (in US\$) Foreign		Rate per container per day or part thereof (in ₹) Coastal		Particulars	Rate per container per day or part thereof (in US\$) Foreign		Rate per container per day or part thereof (in ₹) Coastal	
		Upto 20' in length	Over 20' to upto 40' in length	Upto 20' in length	Over 20' to upto 40' in length		Upto 20' in length	Over 20' to upto 40' in length	Upto 20' in length	Over 20' to upto 40' in length
5.	ICD Import & Export- Loaded or Empty moved by Rail					ICD Import & Export- Loaded or Empty moved by Rail				
	First 7 days	Free	Free	Free	Free	First 3 days	Free	Free	Free	Free
	7-15 days	3.2797	6.5555	143.04	286.07	4-15 days	3.2797	6.5555	143.04	286.07
	16-30 days	3.9515	7.9030	172.30	344.60	16-30 days	3.9515	7.9030	172.30	344.60
	31-45 days	7.9030	15.8061	344.60	690.83	31-45 days	7.9030	15.8061	344.60	690.83
	Thereafter	15.8061	31.6122	690.83	1380.03	Thereafter	15.8061	31.6122	690.83	1380.03

3. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of JNPT dated 5 April 2018 and 2 July 2018 was forwarded to the concerned users/ user organisations seeking their comments. In this regard, some of the user associations viz., Mumbai and Nhava-Sheva Ship-Agents' Association (MANSA), Indian National Shipowner's Association (INSA) and Indian Merchant Chamber (IMC) have furnished their comments. These comments were forwarded to the JNPT as feedback information. The JNPT has responded vide its letter dated 30 August 2018 and 16 May 2019.

4. Subsequently, the JNPT vide its letter dated 9 August 2018 has furnished the Minutes of the meeting held on 6 July 2018 under the aegis of Chairman, JNPT and representatives from Government of India and the discussions that had transpired between JNPT officials and users during the said meeting. From the Minutes of the meeting, it seen that, it has been discussed, interalia, to reduce free period of ICD Containers in a phased manner and that based on the feedback from CONCOR and other Container Terminal Operators, some ICD's would be identified, for reduction of free period for import Containers.

5. The JNPT was requested vide our letter dated 19 July 2018 to furnish some information/ clarification. Accordingly, the JNPT vide its letter dated 11 September 2018 has responded. The information sought by us and reply furnished by JNPT is tabulated below:

Sl. No.	Information sought by us	Reply from JNPT
(i)	List down the reasons on account of which the dwell time of containers moved by rail mode is higher than that of road mode.	Reasons for higher Dwell time for Rail Containers are as follows: (i) Private Rake operators have low volumes and hence they take longer time to complete rakes. (ii) Some ICDs have low volume of exports and imports cargo. (iii) During the time of surge in volume, the train operator CONCOR is unable to mobilize additional rakes.
(ii)	The reduction in free period for ICD Containers from 7 days to 3 days may result in additional income accruing to JNPT. The additional income estimated in this regard to be quantified for the balance tariff validity period up to 31 March 2019.	Additional income estimated due to reduction in free period of ICD containers from 7 days to 3 days is approximately ₹5.52 crores per annum.
(iii)	It may be recalled that in the general revision proposal of JNPT disposed of vide tariff Order no. TAMP/48/2016-JNPT dated 4 January 2017, the income estimated by JNPT at the then proposed level of tariff was same as the ceiling Annual Revenue Requirement (ARR) at ₹ 843.28 crores. In other words, there was no revenue gap between the income as estimated by JNPT at the then proposed level of tariff vis-a-vis, the ceiling ARR. It was based on the said ARR and taking into account the traffic of 2014-15 that the rates were determined by JNPT for the various services to be rendered at JNPT. Considering that the reduction in dwell time may result in additional revenue to the port, the JNPT to propose adjustment in the rates of some other tariff items so that the overall annual revenue to be generated on account of reduction in dwell time, would be within the ceiling ARR as assessed in the January 2017 Order of JNPT to maintain revenue neutral position.	It is to state that TAMP has granted ceiling annual revenue requirement at ₹ 843.28 crores and consequently granted 16% increase in container related charges. However, in the interest of the trade, Port has not increased the rates and maintained the same rates as granted by TAMP in the earlier tariff Order dated 4 April 2014. Hence, it is submitted that even if reduction in dwell time may result in additional revenue to the port there is no need to adjust the rates in some other tariff items so that overall annual revenue generated is within the ceiling ARR in order to maintain the revenue neutral position.

6. A joint hearing on the case in reference was held on 20 July 2018 at the Office of this Authority in Mumbai. At the joint hearing, the JNPT and the users/ user organisations have made their submissions.

7.1. Thereafter, the JNPT vide its letter dated 15 December 2018 has stated that in view of the dissent from Mundra and Pipavav to the proposal of Ministry of Shipping (MOS) to reduce the free storage period on pan India basis, JNPT has requested MOS for retaining the duration of existing free period for rail containers.

7.2. Thus, considering that other private operators have refused to reduce the free period of ICD containers, the JNPT has also conveyed to the MOS that it would like to retain the existing free period for ICD containers and awaited communication on the matter from MOS. Accordingly, the JNPT requested us to keep its subject proposal in abeyance till further orders from MOS.

8. In this connection, after a reminder dated 09 April 2019, the JNPT vide its letter dated 16 May 2019 has made the following submissions:

- (i) In reply to Ports letter JNP/TRAFFIC/ICD/2018/2877 dated 6.11.2018, Ministry of Shipping vide letter no. PD-14033/30/2018-PD-V dated 12.12.2018 has replied that the proposal of reduction in Dwell time of cargo coming by railway can be explored phase-wise and in Phase-I only for 3 ICD's of CONCOR, the free time be reduced to 4 days.
- (ii) As per Ministry's directions, JN Port has requested CONCOR for identification of 3 ICD's destination for reduction in free period and inform JNPT for approaching TAMP. Reply from CONCOR is still awaited.

9.1. After the above said communication from JNPT, inspite of reminders, we have not heard anything from JNPT till date.

9.2. It is noteworthy that based on a specific request made by JNPT, it was decided to keep the proposal of JNPT in abeyance. Till date we have not heard from JNPT regarding identifying of 3 ICDs of CONCOR to explore phased reduction in Dwell time of cargo coming by railways. It is relevant here to mention that the initial proposal was filed by JNPT in April 2018. A joint hearing on the case was also held on 20 July 2018. The proposal of JNPT has been pending with us for want of information and clarity from JNPT for more than 17 months.

9.3. Accordingly, the JNPT was requested vide our letter dated 19 July 2019 to furnish the response of CONCOR on identification of 3 ICD's of CONCOR for reduction of free period by 31 July 2019, failing which, the Authority may be constrained to close the case for want of requisite information from JNPT. In spite of the above communication, the JNPT has not furnished the requisite information, so far.

10.1. The proposal has been pending with us for more than 17 months. Given that timelines have been prescribed under various Guidelines for passing of Orders in a time bound manner, it is not felt appropriate to keep the proposal of JNPT pending indefinitely, for want of information from the Port. Even after giving a final opportunity to JNPT, the JNPT has not responded. In view of the above position, this Authority is constrained to close the case for want of requisite information from JNPT.

10.2. Any communication to be received from JNPT on the subject proposal in the future, if any, shall be treated afresh.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./279/19]